

अमर उजियारा

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष-7

अंक-7

सोमवार, 7 जून 2021

हल्द्वानी (नैनीताल)

मूल्य 5/- रुपया

पृष्ठ 8

कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु अधिक से अधिक सैम्पलिंग बढ़ाई जाये : मुख्यमंत्री

अमर उजियारा संवाददाता

रूद्रपुर। एक दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने एपीजे अब्दुल कलाम सभागार कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जिले में कोविड संक्रमण की रोकथाम, उपचार एवं उससे बचाव आदि हेतु किए जा रहे कार्यों के साथ ही आगामी मानसून काल के मद्देनजर पूर्व तैयारी तथा जनपद में संचालित विकास कार्यों की विस्तृत रूप से जानकारी ली। मा0 मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु अधिक से अधिक सैम्पलिंग बढ़ाई जाए। इस हेतु सभी ग्राम सभाओं में मेडिकल टीम जाकर जांच करे। जांच के दौरान लक्षण वाले प्रत्येक व्यक्ति को तत्काल दवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं ग्राम स्तर पर निगरानी टीम को और अधिक एक्टिव रखते हुए संक्रमण की रोकथाम हेतु कार्य करें। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराना सुनिश्चित करें। मा0 मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के साथ ही आगामी वर्षा के दौरान जल जनित रोग, डेंगू की रोकथाम हेतु व्यापक स्तर पर सभी नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निकाय व पंचायती विभाग सेनेटाइजेशन का कार्य लगातार जारी रखें, साथ ही जनता को इसके प्रति जागरूक भी करें। समीक्षा के दौरान मा0 मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में कोरोना से संबंधित आवश्यक दवा की किट का भी वितरण शीघ्रता से कराया जाये। मा0 मुख्यमंत्री ने सभी विधायक एवं अन्य

जनप्रतिनिधियों से कहा कि गांव में जाकर लगातार दवाई एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी लेते रहें। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु कड़ाई से कर्फ्यू का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ब्लैक फगस की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने 15 हजार इंजेक्शन की व्यवस्था कर ली है एवं कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार अस्पतालों के साथ ही होटल, धर्मशाला की भी व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कन्ट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया, कन्ट्रोल रूम की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए होम आईशोलेशन में रह रहे मरीजों से विडियो कॉल के माध्यम से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली एवं जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण में जो बच्चे अनाथ हो गये हैं ऐसे बच्चों को 3000 रु0 प्रतिमाह दिए जायेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे अनाथ/असहाय बच्चे जब तक बालिग न हो तब तक जिलाधिकारियों की देखरेख में रहें ताकि उनकी सम्पत्ति को कोई भी नुकसान न पहुंचा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण में बजट की कोई कमी नहीं है जिसके लिए जिलाधिकारी को भी अधिकार दिये गये हैं कि वह अपने फण्ड से भी इस महामारी में खर्च कर सकते हैं। समीक्षा के दौरान मा0 मुख्यमंत्री द्वारा आगामी मानसून काल के मद्देनजर सम्बन्धित अधिकारियों से जानकारी लेते हुए कहा कि आगामी मानसून के लिए क्या तैयारियां की गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने हेतु पूर्व तैयारी करते हुए अलर्ट रहें तथा किसी भी



प्रकार की आपदा की घटना होने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य किए जाये, सभी तहसील व थाना स्तर पर आवश्यक उपकरण राहत पैकेट आदि की भी व्यवस्था के साथ ही राहत कैम्प चिह्नित कर उनमें आवश्यक व्यवस्था पूर्व से रखी जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए आपसी सहयोग से कार्य करें। विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने पेयजल, ऊर्जा विभाग, लोक निर्माण विभाग,सिंचाई समेत विभिन्न कार्यदाई संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह निर्माण कार्यों को समयबद्धता से पूर्ण करें। अधिकारी मुख्यालय में न बैठकर फील्ड में जाकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं, कार्य धरातल पर दिखने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि एक दूसरे के पूरक हैं वह मिलकर

कार्य कर जिले को विकास के क्षेत्र में आगे ले जाएं। वह एक टीम भावना के साथ कार्य करें। बैठक में सांसद अजय भट्ट, विधायक राजकुमार तुकराल, राजेश शुक्ला, हरभजन सिंह चौमा, प्रेम सिंह राणा एवं पुष्कर सिंह धामी ने जिले के विकास के संबंध में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिनका राशन कार्ड अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है उन लोगों को भी राशन देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का मकसद है कि प्रदेश में कोई भी भुखा न रहे। बैठक में जिलाधिकारी श्रीमति रंजना राजगुरु व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर ने प्रजेन्टेशन के माध्यम से जिले में कोविड संक्रमण एवं डेंगू की रोकथाम हेतु किए जा रहे कार्यों के अतिरिक्त वर्तमान में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के एवं आगामी मानसून काल के दौरान किसी भी प्रकार की आपदा से

निपटने हेतु की गई पूर्व तैयारी के साथ ही जिले में संचालित विकास कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज, परिवहन मंत्री यशपाल आर्य, शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय, सांसद अजय भट्ट, विधायक राजकुमार तुकराल, राजेश शुक्ला, सौरभ बहुगुणा, प्रेम सिंह राणा, पुष्कर सिंह धामी, आदेश चौहान, कुमाऊं आयुक्त अरविन्द सिंह हयाकि, डीआईजी कुमाऊ अजय रौतेला, मेयर रूद्रपुर रामपाल, जिलाध्यक्ष शिव अरोरा, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना, नोडल अधिकारी हॉस्पिटल मैनेजेंट बंशीधर तीवारी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 डीएस पंचपाल, अपर जिलाधिकारी उत्तम सिंह चौहान, जगदीश चन्द्र काण्डपाल के साथ ही कोविड से सम्बन्धित नोडल अधिकारी व सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

एस.डी.एम ने किया कोविड सेंटर का निरीक्षण



नैनीताल। माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित याचिका रिट पीटिशन सं0 58/2020 में पारित आदेश के अनुपालन में निगरानी समिति के सदस्य सिविल जज (सी0डि0)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल इमरान मौ0 खान व निगरानी समिति के सदस्य, ए.डी.एम. श्री कैलाश सिंह तोलिया द्वारा दिनांक 04.06.2021 को कोविड केयर सेंटर ओम शान्ति ओम एवं शुगन लॉज गरमपानी, नैनीताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय कोविड केयर सेंटर ओम शान्ति ओम में 04 एवं शुगन लॉज गरमपानी में 01 मरीज भर्ती था। निगरानी समिति द्वारा ईश्वर सिंह, दान सिंह, मदन सिंह व भूपेन्द्र सिंह से बात-चीत कर उनका हाल-पाल, खानपान व चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गयी। चारों मरीज द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं होना बताया गया। निरीक्षण के दौरान एस.डी.एम. कोश्याकुटौली श्री विनोद कुमार उपस्थित थे।

पर्यटन उद्योग से जुड़े कार्मिकों के लिए मांगा आर्थिक सहायता

अमर उजियारा संवाददाता

नैनीताल। लॉकडाउन से प्रभावित पर्यटन उद्योग को विभिन्न क्षेत्रों में छूट व सहायता देने हेतु जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गर्ब्याल ने शासन से अनुरोध किया। श्री गर्ब्याल ने पत्र के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद व सचिव सिंचाई से कहा कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु लॉकडाउन लगाया गया है। जो समय-समय बढ़ाया जा रहा है लॉकडाउन के कारण जनपद में समस्त व्यवसायिक गतिविधियां बन्द हैं जिससे पर्यटन उद्योग से जुड़े कार्मिकों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।

समय-समय पर इनके द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किये जानेकी मांग की जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम हेतु प्रदेश में लागू लॉकडाउन से प्रभावित पर्यटन उद्योग में पड़े प्रतिकूल के कारण पर्यटन क्षेत्र से जुड़े नाव चालक, पैडिल बोर्ड चालक, अस्थाई दुकाने, रिक्शा, घोडा खच्चर, पर्यटन गाइड कार्मिकों व होम-स्टे संचालकों को गत वर्ष की भांति आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। श्री गर्ब्याल ने सचिव सिंचाई से पंजीकृत नाव संचालकों का वार्षिक पंजीकरण/ लाईसेन्स शुल्क माफ किये जाने का भी अनुरोध किया।



सम्पादकीय

चुनौतियों के बीच

अभी तक देखने में यह आया है कि व्यावसायिक बैंक के रख के कारण नीतिगत दरों में कमी का फायदा लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी है कि उद्योगों को तत्काल मदद दी जाए। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने इस बार भी नीतिगत दरों में बदलाव नहीं कर उदार रख का संकेत दिया है। यह लगातार छठा मौका है जब रेपो दर चार और रिवर्स रेपो दर साढ़े तीन फीसद पर ही रखी गई है। इस वक्त केंद्रीय बैंक के सामने बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की है। साथ ही महंगाई को भी काबू में रखना है। जाहिर है, ऐसे में ज्यादा जोखिम नहीं लिए जा सकते। महामारी की दूसरी लहर के कारण ज्यादातर राज्यों में डेढ़ महीने की बंदी से कारोबारी और औद्योगिक गतिविधियां एक बार फिर प्रभावित हो गई हैं। दो महीने पहले ही मौद्रिक नीति समिति ने आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए जो कदम उठाए थे, उन्हें इससे थक्का लगा है। इसलिए मौद्रिक समिति को आर्थिक वृद्धि का अनुमान साढ़े दस से घटा कर साढ़े नौ फीसद करना पड़ा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था में तेजी लाना कम चुनौती भरा काम नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कारोबारी गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए कई क्षेत्रों को मदद की दरकार है। केंद्रीय बैंक ने इस जमीनी हकीकत को बूझा है। इसीलिए बैंक ने इस बार ज्यादा ध्यान पर्यटन कारोबार और इससे जुड़े क्षेत्रों को खड़ा करने पर दिया है। रिजर्व बैंक ने उड्डयन क्षेत्र से जुड़ी बुनियादी सेवाएं देने वालों, यात्राएं आयोजित करने वाले एजेंटों, किराए पर वाहन देने वालों, आयोजन कराने वाली कंपनियों, आपूर्ति शृंखला से जुड़ी सेवाओं, ब्यूटी पार्लर, जिम व स्पा आदि चलाने वालों को रेपो दर पर ही तीन साल के लिए कर्ज देने का एलान किया है। इसके लिए केंद्रीय बैंक पंद्रह हजार करोड़ रुपए जारी करेगा। इसके अलावा लघु उद्योग विकास बैंक को भी सोलह हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ताकि वह छोटे उद्योगों को कर्ज दे सके। केंद्रीय बैंक की यह पहल आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने में बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। लेकिन इसके लिए व्यावसायिक बैंकों को रुचि लेनी होगी और साथ ही थोड़ा जोखिम भी उठाना पड़ेगा। अभी तक देखने में यह आया है कि व्यावसायिक बैंक के रख के कारण नीतिगत दरों में कमी का फायदा लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी है कि उद्योगों को तत्काल मदद दी जाए।

अर्थव्यवस्था की फिक्र

यू तो कोविड संकट से पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का रुझान देखा जा रहा था, लेकिन अप्रत्याशित कोरोना संक्रमण ने उसे बड़ी चोट दी है। वित्तीय वर्ष 2020 में विकास दर माइनस 7.3 रही है। यह अप्रत्याशित नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में विकास दर में माइनस तेईस प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी, जो बाकी की तीन तिमाहियों में संभली है। चौथी तिमाही में विकास दर का धनात्मक होना अच्छा संकेत कहा जा सकता है। दरअसल, जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही थी, दूसरी लहर की भयावहता ने देश की आर्थिकी को बड़ी चोट दी है। इस बार की लहर का खासा असर ग्रामीण इलाकों में देखा गया। जब मांग घटी तो अर्थव्यवस्था का प्रभावित होना लाजिमी था। यही वजह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2022 तक तेजी से उभरने के जो आकलन किये जा रहे थे, दूसरी लहर ने उन पर पानी फेर दिया है। जाहिरा सी बात थी कि कोरोना संकट के चलते अनिश्चय के बीच लोगों ने अपने खर्चों में कटौती की है। यही वजह है कि उपभोक्ता उत्पादों की खरीद में गिरावट आई है। घरेलू उपयोग के उत्पादों मसलन कारों, मोबाइल आदि की खरीद में गिरावट आई है और पेट्रोल की खपत भी घटी है, जिसका प्रभाव यह हुआ

कि देश में रोजगार के अवसरों में संकुचन हुआ। यही वजह है कि आकलन लगाया गया है कि देश में दूसरी लहर के दौरान एक करोड़ रोजगार खत्म हुए हैं और बेरोजगारी की दर में तेजी से वृद्धि हुई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान 97 फीसदी लोगों की आय में गिरावट आई है। निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को महामारी से पूर्व की अवस्था में लौटने में कुछ वक्त लगेगा। बहरहाल, यह नहीं भुलाया जा सकता कि देश की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2016-17 से ही गिरावट का ट्रेंड दिखने लगा था, जो देश में मंदी की आहट का संकेत भी था। बहरहाल, महामारी के संकट में देश के करोड़ों लोग फिर से गरीबी की दलदल में धंस गये हैं। कोरोना संकट के पहले दौर में सरकार ने कुछ बड़े राहत पैकेज दिये थे। महामारी के दौरान सरकार के आय के स्रोतों का भी संकुचन हुआ है। लिहाजा सरकारी खजाने की स्थिति भी खास उत्साहजनक नहीं है। सरकार को कुछ मौद्रिक उपाय तो करने ही होंगे, जो लोगों के हाथ में नकदी बढ़ाएं, ताकि खर्च बढ़ने से उपभोग को बढ़ावा मिल सके। इससे उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और जीडीपी की स्थिति में भी सुधार होगा। बहरहाल, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हालिया आर्थिक आंकड़े उस संकट काल के हैं, जिसमें पूरी दुनिया कराह रही है।

फिर भी सरकार को राजकोषीय घाटे को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। वह भी ऐसे वक्त में जब दूसरी लहर में संक्रमण दर में तो गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन अभी तीसरी लहर की आशंका भी बलवती हो रही है। हमारे लिये यह राहत की बात होनी चाहिए कि खेती के प्राणवायु मानसून ने देश में दस्तक दे दी है और उसके सामान्य होने की बात कही जा रही है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना महामारी के दौरान केवल कृषि क्षेत्र ही वह सेक्टर था, जिसने चारों तिमाही के दौरान साढ़े तीन से साढ़े चार फीसदी की विकास दर बनाये रखी। बाकी सेवा क्षेत्र, पर्यटन, विनिर्माण व उद्योगों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई थी। कह सकते हैं कि कृषि सेक्टर ने देश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को संबल दिया। इसके बूते ही देश के करोड़ों गरीबों को मुफ्त अनाज संकट के इस दौर में उपलब्ध कराया जा सका। ऐसे में सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि आय के नये स्रोत तलाशें और आम आदमी के हाथ में ज्यादा नकदी पहुंचाने की व्यवस्था करे ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद मिल सके। यहां यह भी जरूरी है कि देश में जल्द से जल्द टीकाकरण कार्यक्रम को पूरा किया जाये ताकि स्थिति सामान्य होने से अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों को गति मिल सके।

आयुर्वेद और एलोपैथी प्रतिद्वंद्वी नहीं सहयोगी बनें

कृष्णमोहन झा

यह नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश जब कोरोना के भयावह प्रकोप के कारण त्राहि त्राहि कर रहा है तब योगगुरु बाबा रामदेव और एलोपैथिक चिकित्सकों के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। इस अप्रिय जुबानी जंग की शुरुआत बाबा रामदेव ने ही की है जिनका विवादों से हमेशा ही चोली दामन का साथ रहा है। बाबा रामदेव यह सिद्ध करने पर तुले हुए हैं कि देश में जिन लाखों कोरोना संक्रमित लोगों की प्राण रक्षा संभव नहीं हो सकी है उनमें से अधिकांश का एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से उपचार किया गया था जबकि जिन कोरोना संक्रमितों ने उपचार के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का सहारा लिया उनमें से प्रायः सभी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। बाबा रामदेव अपने बयानों से यह भी सिद्ध करना चाहते हैं कि देश में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जो टीके लगाए जा रहे हैं उनकी उपयोगिता भी असिद्ध नहीं है क्योंकि टीके लगवाने के बावजूद एक हजार एलोपैथिक चिकित्सकों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो चुकी है। बाबाजी के बयानों से यह ध्वनि निकलती है कि लोगों की कोरोना संक्रमण से रक्षा करने हेतु उनके पतंजलि संस्थान में तैयार की गई दवा कोरोना के टीकों से कहीं अधिक विश्वसनीय है। बाबा रामदेव के इन बयानों पर देश के प्रख्यात एलोपैथिक चिकित्सकों और उनके प्रतिनिधि संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति जताते हुए उनके विरुद्ध कानूनी लड़ाई की शुरुआत भी कर दी है परंतु बाबा रामदेव अपने बयानों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं बल्कि अब तो उन्होंने यह चुनौती भी दी है कि कोई ताकत उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। यह चुनौती उन्होंने देश में किस कानूनी एजेंसी को दी है यह तो बाबाजी ने स्पष्ट नहीं किया है परंतु भयावह कोरोना संकट के दौरान बाबा रामदेव और एलोपैथिक चिकित्सकों के बीच प्रारंभ हुए इस अवांछनीय अप्रिय

विवाद में केंद्र सरकार की तटस्थता ने बाबा रामदेव को रज्जितर मुद्रा में ला दिया है। बाबा रामदेव के हौसले अब इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे एलोपैथिक चिकित्सकों के साथ अपनी इस लड़ाई में खुद को अजेय मान चुके हैं। बाबा रामदेव के किसी बयान से विवाद की स्थिति निर्मित होने का यह पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के बारे में दिए गए बयानों से विवाद खड़े होते रहे हैं परंतु उनका यह विवादास्पद बयान दर असल ऐसे समय आया है जब देश के अनेक राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप का शिकार होकर हजारों लोग एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से ही अपना उपचार करा रहे हैं। बाबा रामदेव को शायद यह जानकारी भी नहीं है कि विभिन्न राज्यों में स्थित आयुर्वेद चिकित्सा संस्थानों में कोरोना के गंभीर संक्रमण से ग्रस्त लोगों को भर्ती ही नहीं किया जा रहा है। बाबा रामदेव क्या यह नहीं जानते कि कोरोना के गंभीर संक्रमण के मरीज एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के जरिए स्वस्थ होकर बड़ी संख्या में घर लौट रहे हैं। गौरतलब है कि रामदेव के द्वारा कुछ समय पूर्व दिए गए एक बयान के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा हर्षवर्धन ने उन्हें एक पत्र लिखकर इस तरह के आपत्तिजनक बयान न देने का परामर्श भी दिया था। आश्चर्य की बात यह भी है कि कुछ समय पूर्व बाबा रामदेव ने पतंजलि संस्थान द्वारा तैयार दवा कोलोनिल को लांच करने हेतु आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा हर्षवर्धन को आमंत्रित किया था जो स्वयं एक प्रसिद्ध एलोपैथिक चिकित्सक रहे हैं। यह बात अलग है कि उक्त समारोह में डा हर्षवर्धन की मौजूदगी पर भी विवाद उत्पन्न हो गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि केंद्र में और विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी आमतौर पर उन्हीं मंत्रियों को सौंपी जाती रही है जिन्होंने अतीत में एलोपैथिक

चिकित्सा पद्धति में उपाधि अर्जित की है। बाबा रामदेव से यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि अगर वे आयुर्वेद को एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से बेहतर मानते हैं तो उन्होंने कभी यह मांग क्यों नहीं की की केंद्र में और राज्य सरकारों में स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी आयुर्वेद में उपाधि प्राप्त चिकित्सकों को सौंपी जानी चाहिए। केंद्र में आयुष मंत्रालय का गठन अवश्य किया गया है परन्तु केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक बयान हमेशा डा हर्षवर्धन द्वारा दिए जाते हैं जो एक एलोपैथिक चिकित्सक रहे हैं। निश्चित रूप से यह समय इन सब मुद्दों पर विचार करने का नहीं है परंतु बाबा रामदेव ने इस समय एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के विरुद्ध जिस बहस की शुरुआत की है उस बहस के लिए यह समय कदापि उपयुक्त नहीं है। वर्तमान में तो सर्वोपरि आवश्यकता इस बात की है कि जिस किसी भी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जानलेवा कोरोनावायरस के संक्रमण से ग्रस्त व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने में सफलता मिलती है उसको न केवल प्राथमिकता प्रदान की जाए बल्कि उस उस चिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञों का पूरा सम्मान किया जाए। जिन एलोपैथिक चिकित्सा विशेषज्ञों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमितों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का अपना फर्ज निभाया है वे निःसंदेह सराहना और सम्मान के हकदार हैं और अगर आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी के माध्यम से कोरोना संक्रमितों की प्राण रक्षा संभव हो सकी है तो बाबा रामदेव भी साधुवाद के हकदार हैं परन्तु यह समय बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच द्वंद्व युद्ध के लिए कर्तव्य उपयुक्त नहीं है। बाबा रामदेव यह दावा कर रहे हैं कि देश में केवल 10 प्रतिशत कोरोना संक्रमित एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से स्वस्थ हुए हैं और बाकी 90 प्रतिशत कोरोना संक्रमितों को योग और आयुर्वेद ने स्वस्थ किया है। इस दावे की जांच के लिए भी यह समय उपयुक्त नहीं

है। मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले देश को कोरोना संकट से पूरी तरह मुक्त हो जाने दीजिए फिर देश यह तय कर लेगा कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति और योग- आयुर्वेद में से किस पद्धति से स्वस्थ होने वाले लोगों का प्रतिशत अधिक था। यह बहस इस समय असामयिक बहस उन चिकित्सा विशेषज्ञों का ध्यान भंग कर सकती है जो अपनी जान जोखिम डाल कर रात दिन कोरोना संक्रमितों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के पुनीत कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के लिए चुनौती पेश कर के स्वयं बाबा रामदेव ने खुद अपना ध्यान भंग किया है जबकि वे अगर अपने समय और अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने में कारगर आयुर्वेदिक औषधियों के अनुसंधान के लिए करें तो देश को अधिक राहत मिलेगी। बाबा रामदेव और एलोपैथिक चिकित्सा विशेषज्ञों के बीच जारी यह लड़ाई आगे जाकर कब थमेगी या कौन सा रूप लेगी यह कहना अभी मुश्किल है। जब बाबा रामदेव अपने बयानों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं तो इस बात की संभावना तो नहीं के बराबर है वे एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के बारे में दिए गए कथित रूप से आपत्तिजनक बयानों के लिए माफी मांगने की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मांग स्वीकार कर लेंगे। उधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की आपत्ति के बाद बाबा रामदेव ने एसोसिएशन से 25 सवालों के जवाब देने को कहा है जिसपर अपनी प्रतिक्रिया में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष जे ए जयलाल ने कहा है कि वे इन सवालों के संबंध में आयुर्वेद के किसी भी डाक्टर से बात करने के लिए तैयार हैं परंतु रामदेव कोई डाक्टर नहीं हैं। डा जयलाल का कहना है कि अगर बाबा रामदेव का पक्ष सही है तो केंद्र सरकार को एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए

अन्यथा रामदेव पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मामला दर्ज करना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ही महासचिव डा जयेश लेले ने आरोप लगाया है कि बाबा रामदेव कोरोना वैक्सीन लेने के बाद 10 हजार चिकित्सकों की मौत होने की जो बात कह रहे हैं उसके पीछे उनकी यह मंशा कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों के बीच भय का माहौल निर्मित करने की है। इस तरह वे अपनी दवा को प्रचारित करना चाहते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि अब यह प्रमाणित हो चुका है कि कोरोना वैक्सीन इस वायरस के संक्रमण से मानव शरीर की रक्षा करने में सक्षम है। देश में एलोपैथिक चिकित्सक स्वास्थ्य मंत्रालय, आई सी एम आर और नेशनल टास्क फोर्स की गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं ऐसे में बाबा रामदेव अपने बयानों से सरकारी आदेशों को चुनौती दे रहे हैं। बाबा रामदेव और एलोपैथिक चिकित्सकों के प्रतिनिधि संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच जारी इस विवाद को थामने के लिए भी तक केंद्र सरकार की ओर से पहल किए जाने के कोई संकेत नहीं मिले हैं परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना इस विवाद का सुखद पटाक्षेप होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा हर्षवर्धन को इस अप्रिय विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की पहल करनी होगी। अगर दोनों ही पक्ष इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर अपने रुख पर अडिग रहे आते हैं तो यह स्थिति एक जानलेवा वायरस के विरुद्ध हमारी लड़ाई को कमजोर कर सकती है। देश अभी कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप से मुक्त नहीं हुआ है और तीसरी लहर को भी अवश्यंभावी बताया जा रहा है ऐसे में एलोपैथी बनाम आयुर्वेद का के इस अप्रिय विवाद को यहीं विराम देकर तीसरी लहर की तैयारी पर ही सारा ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। यही सारा देश चाहता है।

शासन की गाइड लाइन को सख्ती से पालन कराया जाये : डीएम

नैनीताल। जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में पाँच वे चरण का कोविड कर्फ्यू 08 जून से 15 जून प्रातः 06 बजे तक बढ़ाया जाता है। उन्होंने जनपद में कोविड कर्फ्यू के दौरान शासन की गाइडलाइन का सख्ती से साथ अनुपालन कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी श्री गर्ब्याल ने कहा कि 15 जून सुबह 06 बजे तक कोविड कर्फ्यू बढ़ाया जाता है। उन्होंने बताया कि जनपद में परचून (किराना) की दुकानें, जनरल स्टोर सप्ताह में 02 दिन 09 जून व 14 जून को प्रातः 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक खुलेंगी तथा स्टेशनरी एवं किताबों की दुकानें भी 09 जून व 14 जून को प्रातः 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक खुलेंगी। सरकारी गल्ला, सब्जी, दूध मीट आदि की दुकानें प्रातः 08 बजे से लेकर प्रातः 12 बजे तक प्रत्येक दिन नियमित खुलेंगी। फोटो स्टेट की दुकानें, टिम्बर मर्जेन्ट की दुकानें

09 जून (बुधवार) को प्रातः 08 से दोपहर 01 बजे तक इसी तरह खाद्य पेकेजिंग, कपड़ा, रेडीमेड, दर्जी, चर्म की दुकानें, साईकिल स्टोर, औद्योगिक, मोटर पाटर्स एवं ड्राई क्लीनिंग की दुकानें 11 जून (शुक्रवार) को प्रातः 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक खुलेंगी। साथ ही पशुचारा, कीटनाशक, खाद, बीज की दुकानें, भण्डारण परिवहन आदि की भी सुबह 08 से 11 बजे तक अनुमति रहेगी। पेट्रोल, डीजल पम्प एवं रसोई गैस, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। घरेलू गैस एवं टैंकर से पेयजल का वितरण भी होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित क्षेत्र जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, दवा की दुकानें, चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेन्टर भी 24 घण्टे खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है मानकों का पालन करना होगा। बैंक प्रातः 10 बजे से दोपहर 02 बजे तक खुलेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में

मदिरा की दुकानें 09 जून, 11 जून व 14 जून को प्रातः 08 बजे से 01 बजे तक खुलेंगी। बार अग्रिम आदेश तक बन्द रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी माल वाहक वाहनों को जनपद एवं अन्तर-राज्यीय आवागमन के साथ सामाग्री के परिवहन की अनुमति होगी। तथा सभी माल वाहक वाहनों को सामाग्री लोड एवं अनलोड करने दैनिक रात्रि 09 बजे से प्रातः 05 बजे तक अनुमति होगी। कोरोना कर्फ्यू अवधि में सभी विभागीय कर्मचारियों व प्रेस प्रतिनिधियों के लिए उनके संस्थान द्वारा जारी परिचय-पत्र ही पास होगा। इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें जनपद में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि में अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए क्वारंटीन सेन्टर

में पूरी करनी होगी। श्री गर्ब्याल ने बताया कि शादी समारोह में केवल 20 लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव के साथ ही अनुमति होगी। इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी। नई एसओपी के अनुसार आपातकालीन आवश्यकता वाले रोगियों व उनके तीमारदारों को आने-जाने के लिए डॉक्टर की पर्ची दिखानी होगी। वैक्सीनेशन के लिए घरों के बाहर निकलने पर उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा। ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा। मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। जनपद में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। निकाय सार्वजनिक स्थलो, आवसीय क्षेत्रों, बस अड्डों, मंडियों आदि को निरंतर सेनेटाइज करते रहेंगे। शराब की दुकानें और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा ड्रग्स, क्लीनिक्स, पैथ लैब, आदि को छूट दी गयी है। उन्होंने बताया कि होटल

एवं रेस्टोरेंट में सिर्फ किचन सर्विस चलेगी तथा होटल एवं रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि आवश्यक सामान लाने और ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के ऑफिस आने-जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से वाहनों की आवाजाही हेतु यात्रा टिकट के साथ डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य होगा। आपातकालीन स्थिति में आर्टो-टैक्सी को आवाजाही में छूट और मरीजों एवं तीमारदारों के वाहनों को भी रियायत दी गई है। मेडिकल कर्मचारियों के वाहन, वैक्सीनेशन और कोरोना की टेस्टिंग के लिए जाने के लिए भी रियायत होगी। आवश्यक सेवाओं और कोविड-19 से जुड़ी सेवाओं वाले सरकारी-निकायों के वाहनों को चलने की अनुमति होगी। उन्होंने शासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

मेला अधिकारी दीपक रावत व अपर मेला अधिकारी हरबीर सिंह को संतों ने किया सम्मानित



हरिद्वार। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामण्डलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने कुंभ मेला सकुशल संपन्न कराने में निर्णायक भूमिका निभाने वाले कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत एवं अपर मेलाधिकारी हरबीर सिंह को शॉल ओढ़ाकर व गंगाजली भेंटकर सम्मानित किया। राममंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले परमहंस स्वामी वामदेव महाराज के जीवन पर आधारित पुस्तक भी संतों ने अधिकारियों को भेंट की और पावनधाम के समीप बनाए जा रहे स्वामी वामदेव चौक को शीघ्र पूरा कराने की मांग की। दोनों

अधिकारियों को उनके आवास पर सम्मानित करने के दौरान महामण्डलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने कहा कि कोरोना काल में कुंभ मेले को सकुशल संपन्न कराना मेला अधिकारी दीपक रावत व अपर मेला अधिकारी हरबीर सिंह की कार्यकुशला को दर्शाता है। उनके द्वारा संत महापुरुषों, आश्रम, अखाड़ों, मठ मंदिरों के प्रबंधकों से व्यवस्थाओं को लेकर लगातार समन्वय स्थापित किए जाने से ही कुंभ मेले के आयोजन में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। दोनों ही अधिकारी हमेशा ही अपनी कार्यकुशलता व कर्मठता से संत समाज को भी

प्रभावित करते रहे। कोरोना काल में कुंभ मेले को सकुशल संपन्न कराना दोनों ही अधिकारियों की बड़ी उपलब्धि है। ऐसे अधिकारियों को मनोबल व उत्साह बढ़ाया जाना जरूरी है। स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने कहा कि कई तरह के व्यवधान उत्पन्न होने पर दोनों अधिकारियों ने जिम्मेदारी का परिचय देते हुए मौके पर पहुंचकर समस्याओं का समाधान कराया। कुंभ मेले के दौरान संत समाज को दोनों अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिला। जिसके लिए मेला अधिकारी दीपक रावत व अपर मेला अधिकारी हरबीर सिंह बधाई व आशीर्वाद के पात्र हैं। मेला अधिकारी दीपक रावत ने कहा कि कोरोना के कारण उत्पन्न हुई विपरीत परिस्थितियों में कुंभ मेले जैसे विशाल आयोजन को सकुशल संपन्न कराना बेहद चुनौतीपूर्ण था। लेकिन संत समाज के सहयोग से सभी शाही स्नान सकुशल संपन्न हुए। अपर मेला अधिकारी हरबीर सिंह ने कहा कि वे सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें संत महापुरुषों की सेवा का अवसर मिला। संत महापुरुषों के सानिध्य, आशीर्वाद व सहयोग से ही मेला प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाया। इस दौरान स्वामी विष्णु देवानंद, स्वामी कैलाशानंद, स्वामी आत्मानंद, साध्वी योगी श्रद्धानाथ आदि संत मौजूद रहे।

45 लोगों ने किया स्वैच्छिक रक्तदान



ऋषिकेश। भाजपा के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में दूसरों का जीवन बचाने के लिए 45 लोग आगे आए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रत्येक रक्तदाता को गिलोय का पौधा, प्रमाणपत्र और लगातार 8 बार रक्तदान कर चुके पार्षद राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। देहरादून रोड स्थित व्यापार सभा में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्वैच्छिक रक्तदान के लिए पंजीकरण कराने वाले लोगों के हिमोग्लोबिन आदि की जांच की। जांच के उपरांत 45 लोगों ने बारी-बारी से रक्तदान किया। कार्यक्रम आयोजक पूर्व दर्जाधारी मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल ने

बताया पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की रक्तदान की मुहिम चल रही है। उसी के तहत यह शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 45 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ है, जो जख्मरतमंदों के काम आएगा। मौके पर मेयर अनिता ममगाई, जिला संचालक आरएसएस सुदाम सिंघल, जिला अध्यक्ष प्रांतीय व्यापार मंडल नरेश अग्रवाल, ललित कुमार मिश्र, व्यापार सभा अध्यक्ष मनोज कालड़ा, पवन शर्मा, हर्षित गुप्ता, पंकज शर्मा, अनिकेत गुप्ता, दीनदयाल, विनोद भट्ट, कपिल गुप्ता आदि मौजूद रहे। वैक्सीन के दो डोज लगवा चुके लोगों को चारधाम यात्रा की अनुमति मिले ऋषिकेश। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कोरोना वैक्सीन की दो डोज लगवा चुके लोगों को चारधाम यात्रा की अनुमति देने की वकालत की है।

संशोधित होगी राज्य की आपदा एवं पुनर्वास नीति: डा. धन सिंह रावत

- आपदा सचिव को दिये संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट में लाने के निर्देश
- नई नीति में शामिल किये जायेंगे विशेषज्ञ एवं विधायकों के सुझाव
- वर्ष 2012 से अब तक 43 गांवों के 1086 परिवारों का हुआ पुनर्वास
- मंत्री ने लगाई अधिकारियों को फटकार, कहा लम्बित मामलों में लायें तेजी

देहरादून। प्रदेश के आपदा प्रभावित गांवों के पुनर्वास को लेकर उच्च शिक्षा, सहकारिता, प्रोटोकॉल एवं आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आज विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्रों के विधायक भी मौजूद रहे। बैठक की खास बात यह रही कि इसमें विपक्ष के विधायकों ने भी शिरकत कर अपने-अपने क्षेत्रों के आपदा प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर सुझाव रखे। साथ ही विपक्षी विधायकों ने विभागीय मंत्री डा. रावत का आभार जताते हुए कहा कि यह पहला मौका है जब किसी संवेदनशील मुद्दे पर प्रतिपक्ष के विधायकों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया। विभागीय मंत्री ने बैठक में विधायकों द्वारा दिये गये जनहित के सुझावों को शामिल कर प्राकृतिक आपदा संबंधी वर्ष 2011 की विस्थापन/पुनर्वास नीति का संशोधन प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट में

लाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। समीक्षा बैठक में उपस्थित विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों के दैवीय आपदाग्रस्त गांवों एवं परिवारों के शीघ्र विस्थापन की मांग रखते हुए नियमों में शिथिलता लाने संबंधी सुझाव रखे। जिस पर विभागीय मंत्री डा. रावत ने विधायकों को भरोसा दिलाया कि शीघ्र ही आपदा प्रभावितों के विस्थापन संबंधी नीति में संशोधन कराया जायेगा। जिसमें विधायकों एवं विशेषज्ञों के उपयोगी सुझावों को शामिल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि 10 दिन बाद पुनः विस्थापन एवं पुनर्वास प्रकरणों की समीक्षा की जायेगी। विभागीय मंत्री ने अधिकारियों द्वारा बैठक में पुराने एवं आधे-अधूरे आंकड़े प्रस्तुत करने पर फटकार लगाते हुए भविष्य में पूरी जानकारी के साथ बैठक में आने की नसीहत दी। विभागीय मंत्री डा. रावत ने बताया कि राज्य में पुनर्वास नीति 2011 लागू होने पश्चात विभाग द्वारा प्रदेश में अब तक कुल 43 गांवों के 1086 परिवारों



का विस्थापन किया चुका है। जिनके पुनर्वास पर विभाग द्वारा कुल 45 करोड़ 63 लाख 63 हजार 916 रुपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है। समीक्षा बैठक में वर्तमान तक पुनर्वासित परिवारों की जनकारी देते हुए विभागीय सचिव एस.ए. मुरुगेशन ने बताया कि वर्ष 2012 एवं 2015 में रुद्रप्रयाग जनपद के 4 परिवार एवं चमोली जनपद के 07 परिवारों

का पुनर्वास किया। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2017-18 में 4 जनपदों के 177 परिवारों का पुनर्वास किया गया। जिनमें बागेश्वर के 28, चमोली के 67, टिहरी के 26, एवं रुद्रप्रयाग के 56 परिवार शामिल हैं। जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 3 जनपदों के आपदा प्रभावित 151 परिवारों का पुनर्वास किया गया। जिनमें चमोली के 113, बागेश्वर के 18, टिहरी के 20 परिवार

शामिल है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 के तहत 04 जनपदों 360 परिवारों का पुनर्वास किया गया। जिसमें पिथौरागढ़ के 21, टिहरी के 265, बागेश्वर के 5, चमोली के 69 परिवार शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 6 जनपदों के 258 परिवारों का पुनर्वास किया गया। जिनमें टिहरी के 92, उत्तरकाशी के 91, चमोली के 18, नैनीताल के 1, बागेश्वर के 4, पिथौरागढ़ के 52 परिवार शामिल हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3 जनपदों के 129 परिवारों का विस्थापन कर दिया गया है। जिसमें अल्मोड़ा के 4, उत्तरकाशी के 94 और पिथौरागढ़ के 31 परिवार शामिल हैं। बैठक में कपकोट विधायक बलवंत सिंह भौर्याल, यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत, पुरोला विधायक राजकुमार, बदीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट, केदारनाथ विधायक मनोज रावत, थरली विधायक मुन्नी देवी, घनसाली विधायक शक्ति लाल, धारचूला विधायक हरिश धामी, सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास एस.ए. मुरुगेशन, अपर सचिव डा. आनन्द श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव विक्रम सिंह यादव, अनुभाग अधिकारी एस.डी. बेलवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

परियोजना पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए : जिलाधिकारी

नैनीताल। आईआईटी रुड़की और जायका द्वारा जियो फिजिकल सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि जीजीआईसी से सिपाही धारा तक लगभग 200 मीटर की लंबाई में पानी का भूमिगत स्रोत है, जिससे बलियानाला में प्रतिदिन लगभग 8 एमएलडी पानी (निकल रहा) रिस रहा है। जायका और आईआईटी रुड़की द्वारा दिये गये सर्वे आधारित सुझाव पर जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गर्ब्याल ने चिन्हित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर पानी लिफ्टिंग को गठित कमेटी के सदस्यों को जल्द पानी की उपलब्धता

जांचने के लिए दो से तीन स्थानों पर बोरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ज्योलोजिस्ट्स के जो भी सुझाव होंगे, उन पर अमल किया जायेगा। जिलाधिकारी ने मौके पर अधि कारियों को निर्देशित करते हुए कहा इस परियोजना पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए ताकि भूमिगत पानी से नगर में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके साथ ही लगातार बलियानाले में हो रहे धसाव को रोका जा सके इसके साथ ही डीएम ने कहा कि जीआईसी स्कूल से जीजीआईसी स्कूल के बीच

दो से तीन स्थानों पर बोरिंग की जाएगी, जिसके बाद पानी की पर्याप्तता को देखते हुए उसे लिफ्ट करने की योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सुरक्षात्मक दृष्टि से जिन स्थानों पर रिटैनिंग वॉल की आवश्यकता हो, उन स्थानों पर रिटैनिंग वॉल बनायी जाये। उन्होंने कहा कि यदि बोरिंग टैस्टिंग सफल रहा और हम 2 एमएलडी पानी प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो इस पानी को तल्लीताल व एरीज क्षेत्र तक पहुँचाया जायेगा। श्री गर्ब्याल ने कहा कि पानी की उपलब्ध

ता अधिक होने पर शहर कि विभिन्न क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराया जायेगा। श्री गर्ब्याल ने कहा कि बोरिंग की सफलता के आधार पर यदि आवश्यकता पड़ी तो जीजीआईसी व जीआईसी के साथ ही धर्मशाला तक भी जगह-जगह सर्वे कराये जायेंगे। उन्होंने बताया कि नैनीताल शहर को प्रतिदिन 8 एमएलडी पानी की आवश्यकता होती है जबकि लगभग इतना ही पानी बलियानाला क्षेत्र से निकल रहा है। उन्होंने कहा कि यदि हम भूमिगत पानी को टेप करने में सफल रहे तो इससे नगर में

पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी साथ ही लगातार बलियानाले में हो रहे धसाव को रोकने में भी मदद मिलेगी। इस दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रतीक जैन, एडीएम अशोक जोशी, सिंचाई विभाग अधिशासी अभियंता हरीश चन्द्र सिंह, अधिशासी अभियंता जल संस्थान संतोष उपाध्याय, अधिशासी अधिकारी अशोक वर्मा, लोनिवि अधि शासी अभियंता लोनिवि दीपक गुप्ता, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी शैलेश कुमार समेत तमाम अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

50 बेड का आयुर्वेदिक अस्पताल का जल्द होगा मुहूर्त : अजय भट्ट



हल्द्वानी में स्टेडियम के पास उत्तराखंड का सबसे बड़ा 50 बेड का आयुर्वेदिक अस्पताल जल्द मुहूर्त रूप लेकर शुरू होगा नैनीताल उध म सिंह नगर से सांसद अजय भट्ट ने आयुर्वेदिक अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद कार्यदाई संस्था के अधिकारियों को 1 महीने के भीतर अस्पताल के संपूर्ण कार्य पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए हैं सांसद अजय भट्ट ने बताया कि यह अस्पताल आयुर्वेद पंचकर्म होम्योपैथी और नेचुरोपैथी के लिए लोगों में वरदान साबित होगा। बुध वार को स्टेडियम के पास बन रहे तीन मंजिला 50 बेड के आयुर्वेदिक अस्पताल का निरीक्षण करते हुए सांसद अजय भट्ट ने बताया कि इस अस्पताल को भारत सरकार द्वारा 90:10 अनुपात पर बजट

उपलब्ध करा कर 10 करोड़ की लागत से निर्माण कराया जा रहा है। सांसद अजय भट्ट द्वारा कार्यदाई संस्था को अगले माह तक इस अस्पताल को पूर्ण रूप से हैंड ओवर करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान सांसद अजय भट्ट को जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा बताया गया कि यहां एक समय पर 15 डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे जिसमें होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, पंचकर्म और नेचुरल थेरेपी से बीमार मरीजों का उपचार किया जाएगा। इसके साथ ही यहां पहली बार पंचकर्म थेरेपी दिए जाने वाला पहला अस्पताल होगा। राज्य के सबसे बड़े आयुर्वेदिक अस्पताल को लेकर केंद्र व राज्य सरकार की संजीदगी को देखते हुए सांसद अजय भट्ट ने केंद्र व

राज्य सरकार का आभार भी प्रकट किया और यह उम्मीद जताई कि अगले महीने से यह अस्पताल जनता के लिए खोल दिया जाएगा। वर्तमान में कोरोना महामारी को देखते हुए यहां कोरोना की जांच सहित कई अन्य जांच भी की जाएगी। नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि आज के दिन में आयुर्वेद विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है आने वाले दिनों में उत्तराखंड में आयुर्वेद होम्योपैथिक नेचुरोपैथी पंचकर्म पद्धतियों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा मरीजों का बेहतर उपचार हो सकेगा सरकार की इसी मंशा को देखते हुए राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हल्द्वानी में स्थापित हो रहा है सांसद अजय भट्ट ने कहा कि इसके अलावा जिले में दूरस्थ ग्रामीण पहाड़ी इलाकों में 4-4 बेड के आयुर्वेदिक अस्पताल बनाए जा रहे हैं जो कि स्थानीय स्तर पर लोगों का उपचार करेंगे और गंभीर स्थिति में हल्द्वानी स्थित बड़े आयुर्वेदिक अस्पताल में मरीजों को रेफर किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान सांसद अजय भट्ट के साथ जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट मंडल अध्यक्ष विनीत अग्रवाल, पूर्व राज्य मंत्री रेनु अधिकारी, सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण खाती प्रतिभा जोशी दीपक जोशी प्रताप रेकवॉल तथा सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष कुमार तहसीलदार नितेश डागर जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी एमएस गुंजियाल, सहित कई अधिकारी कर्मचारी और कार्यकर्ता मौजूद थे।

अपनी इच्छाओं को त्याग कर बेसहारा को दिया बलिदान

अमर उजियारा संवाददाता

देहरादून। बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने मानव सेवा को ही अपना धर्म कर्तव्य मानकर दिव्यांग बेसहारा की मदद करने के लिए अपनी इच्छाओं को भी त्याग दिया जी हां उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत और बीसीसी आई ए लेवल कोच पूर्व क्रिकेटर गिरीश पटवाल कोरोना महामारी में दिव्यांग जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं देवभूमि दिव्यांग वेलफेयर संस्था के माध्यम से वह हर समय लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं आज एक फोन आया मदद के लिए मैं बहुत परेशान हूँ मेरी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं तो गिरीश पटवाल जी ने बिना समय गवाए पता पूछा और अपने सहयोगियों को फोन किया सामाजिक कार्यकर्ता सोनू कुमार मनीष बुटोला चौहान जी एडवोकेट विनय कुमार जी तुरंत ही पहुँच गए देहरादून पहुँच कर दो लोगों को खाद्य सामग्री जैसे आटा दाल चावल चीनी चाय पत्ती रिफाइंड सरसों का तेल मिर्च मसाले आलू प्याज दवाई सैनिटाइजर मास्क इत्यादि सामान दो परिवारों को दिया अगर आप लोगों को और भी आवश्यकता होगी तो हमें फोन

कीजिएगा हम तुरंत ही आपके सहयोग के लिए पहुँच जाएंगे और भी अगर मोहल्ले में कोई दिव्यांग या ऐसा कोई है जिसके पास खाने को ना हो तो हमें बताइए हम उसके भी मदद करेंगे यह कहना है गिरीश पटवाल वही लोगों को जागरूक करते



हुए उन्होंने कहा अगर किसी को खाने का स्वाद नहीं आता है तो घबराए ना और स्वास्थ्य केंद्र पर जाए डॉक्टर से दवाई वगैरा ले और अपने आप को अलग करें घर में किसी बच्चे से ना मिले किसी व्यक्ति से ना मिले गर्म पानी का नियमित इस्तेमाल करें 2 गज की दूरी बनाकर रखें घर से बिना वजह बाहर ना जाएं जाते हैं तो मास्क अवश्य लगाएं कोशिश करें बाजार से इकट्ठा समान लाएं ताकि बाजार बार-बार ना जाना पड़े हाथों को साबुन से धोते रहें एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं सैनिटाइजर का प्रयोग करें घर पर रहें सुरक्षित रहें खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।

जनपद में शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगो को कोविड -19 वैक्सीनेशन कराने हेतु मोबाईल टीमों लगा दी गई है : जिलाधिकारी

हल्द्वानी । जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि जनपद में शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगो को कोविड -19 वैक्सीनेशन कराने हेतु मोबाईल टीमों लगा दी गई है ताकि सभी लोगो का कोविड टीकाकरण हो सके। वैक्सीनेशन हेतु ब्लाकवार माइक्रोप्लान के तहत रोस्टर के अनुसार टीमों लगाई गई है। मोबाईल टीमों द्वारा 45 वर्ष से ऊपर के लोगो का वैक्सीनेशन किया जायेगा। इन्सिडेन्ट कमांडर/ मुख्य विकास अधिकारी नरेन्द्र सिंह भण्डारी ने बताया कि जनपद में मोबाईल टीमों द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन हेतु रोस्टर के अनुसार विकास खण्ड हल्द्वानी में 09 जून को एडब्लू मंडी गेट में, 10 जून को प्राइमरी उत्तर उजाला में, 11 जून को बट्टीपुरा काठगोदाम में, 12 जून को नई बस्ती में इसी तरह विकास खण्ड रामनगर में 09 जून को जीआईसी ढिकुली में, 10 जून को जीआईसी में देला में, 11 जून को जीआईसी थारी में, 12 जून को प्राइमरी स्कूल उदयपुरी बन्दोबस्ती, 14 जून को प्राइमरी स्कूल

टेडा में इसी तरह रामगढ में 10 जून को पंचायत घर खमोली में, 14 जून को पंचायत घर छीनी में, 17 जून को जीआईसी जौरासी में, 19 जून को पंचायत घर सुयलगाढ में, 09 जून को प्राइमरी स्कूल सतोली में, 11 जून को प्राइमरी सिनोली में, 12 जून प्राइमरी स्कूल सतबुगा में, 15 जून को प्राइमरी स्कूल गल्ला में, 16 जून को प्राइमरी स्कूल काफली में, 18 जून को प्राइमरी स्कूल तल्ला सूपी में, 21 जून को प्राइमरी स्कूल ढोकानेधार में, इसी तरह भीमताल के 10 जून व 11 जून को ग्राम पंचायत बजून में, 14 जून व 15 जून को प्राइमरी स्कूल खमारी में, 17 जून को ग्राम पंचायत अथोडा में, 18 जून व 21 जून को ग्राम पंचायत थपला में, 22 जून को प्राइमरी स्कूल जलाल गांव में, 09 जून को प्राइमरी स्कूल चोरलेख में, 10 जून को पंचायत घर सुन्दरखाल में, 11 जून को प्राइमरी स्कूल सुनकिया में, 12 जून को प्राइमरी स्कूल कनारखा में, 14 जून को प्राइमरी स्कूल हरिनगर अशकोरा गुलजार में,

15 जून को प्राइमरी स्कूल अघरिया में, 16 जून को प्राइमरी स्कूल दानी तल्ला में, 17 जून को प्राइमरी स्कूल कल्पताल में, इसी तरह बेतालघाट में 9 जून को प्राइमरी स्कूल तिवारी खोल में, 09 पंचायत घर सूखा में, 10 जून को सब सेन्टर तिवारी गांव में, 10 जून को जू.हा. हरिनगर में, 11 जून को पंचायत घर में, 11 जून को जीआईसी ठाइखेत में, 12 जून को जू.हा. सोनाली में, 12 जून को जू.हा. बजइडी में 14 जून को जू.हा. नैनीचौक में, 14 जून को प्राइमरी स्कूल पानकटरा में, 15 जून को जू.हा. धंधरेटी व बारगल में, 16 जून को जितुआ पीपल व जोग्यारी में, 17 जून को कांडा व जू.हा. खलाड में, 18 जून को मल्लीपाली व प्राइमरी स्कूल निग्लाट में, 19 जून को प्राइमरी स्कूल डाबर जोशीखोला व पंगुट में, 21 जून को प्राइमरी स्कूल उलगाँव व जख में, 22 जून को जीआईसी लोहाली में, 23 जून को पंचायत घर मल्ला वर्धों में, 23 जून को प्राइमरी स्कूल घुना में, 24 जून को प्राइमरी स्कूल अमल व जीआईसी ऊँचकोट में, 25 जून को तल्ली सेठी व प्राइमरी स्कूल

सनगांव-बसगाँव में, 26 जून को जीआईसी गरजोली व प्राइमरी स्कूल हली हतापा में, 28 जून को चंद्रकोट धुवा व प्राइमरी स्कूल धारी खैरी में, 29 जून को प्राइमरी स्कूल घोड़िया हलसो व पंचायत घर खैराली बुंगा में, 30 जून को प्राइमरी मल्ली सेठी व जीआईसी हलसो कोरड, इसी तरह हल्द्वानी के 09 जून को जीएचएस घोडानाला में, 10 जून, 11 जून व 12 जून को जीआईसी खुरियाखता में, 14 जून, 15 जून व 16 जून को हाट कालिका तिवारी नगर बिन्दुखता में, तथा कोटाबाग में 09 जून को पंचायत घर नाथू नगर में, 10 जून को प्राइमरी स्कूल स्यात में, 11 जून को प्राइमरी स्कूल बधानी में, 12 जून को प्राइमरी स्कूल बांसी में, 15 जून को प्राइमरी स्कूल सौड में, 16 जून को प्राइमरी स्कूल बगड में, 17 जून को अमगढी में, 18 जून को जीएच स्कूल डॉन परैवा, 19 जून को सनारा में तथा 20



जून को प्राइमरी स्कूल रियार में इसी तरह ओखलकाण्डा में मोबाईल वैक्सीनेशन 09 जून को प्राइमरी स्कूल गौनियारों में मोबाईल वैक्सीनेशन किया जायेगा। जिलाधिकारी श्री गर्ब्याल ने लोगो से कोविड वैक्सीन लगाने की अपील की है।

बाल कल्याण विभाग बच्चों की पहचान जल्द करे सुनिश्चित: योगी

✦ कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को हर संभव सरकार करेगी मदद
✦ बच्चों के वयस्क होने तक 4000 मासिक वित्तीय सहायता देगी प्रदेश सरकार
✦ अब तक कि 300 बच्चों की पहचान, बाल ग्रह में किया जायेगा पुनर्वासित

को खोया है। अब तक, 300 बच्चों की पहचान की गई है और काम अभी भी जारी है। जिन अनाथ बच्चों की उम्र

लखनऊ। कोरोना वायरस महामारी के चलते अपने माता-पिता को गंवाने वाले बच्चों के प्रति एक और कदम आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हें दी जाने वाली सहायता में संशोधन किया है। जिन बच्चों के अभिभावक की आय सालाना दो लाख रुपए से कम है, उन्हें मदद की श्रेणी में रखा गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कानूनी या नैसर्गिक रूप से रहे अभिभावकों की वार्षिक आय दो लाख रुपये की सीमा बहुत कम है, इसलिए इसे बढ़ाया जाना चाहिए। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक, एक बच्चे के अभिभावक या देखभाल करने वाले को तब तक 4,000 रुपये की मासिक वित्तीय

सहायता दी जाएगी, जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाता है। जबकि जिन बच्चों के पास देखभाल के लिए कोई नहीं है, उन्हें बाल संरक्षण गृह भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग को ऐसे बच्चों की जल्द से जल्द पहचान करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि इस श्रेणी में आने वाला कोई भी बच्चा इस कल्याण योजना से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में बात करते हुए महिला एवं बाल कल्याण विभाग के निदेशक मनोज राय ने कहा, ऐसे बच्चों की पहचान करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता

दस साल तक है और परिवार में देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, ऐसे बच्चों को उत्तर प्रदेश के पांच राजकीय बाल गृह बाल आश्रय गृह में पुनर्वासित किया जाएगा। ये शेल्टर होम मथुरा, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा और रामपुर में हैं। कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। इन बच्चों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और अटल आवासीय विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के



अनाथ बच्चों की शिक्षा वित्तीय कारणों से बाधित न हो। राज्य सरकार की अभ्युदय योजना के तहत ऐसे बच्चों की उच्च शिक्षा की सुविधा के लिए लैपटॉप और

टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के तहत लड़कियों को शादी के लिए योगी सरकार 1,01,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

योगी से अच्छा सीएम नहीं मिल सकता : स्वतंत्र देव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश भाजपा में सियासी खींचतान के बीच प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता। कोई भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा परिश्रमी और ईमानदार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में सीएम योगी ने कानून का राज स्थापित किया है। स्वतंत्र देव का बयान उस समय आया जब प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने से लेकर कैबिनेट विस्तार होने तक की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे समय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके पहले रविवार को भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह ने लखनऊ में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। मुलाकात से पहले उन्होंने मीडिया को दिए गए बयान में कहा कि यूपी सरकार व संगठन इस समय अच्छा काम कर रहे हैं। कैबिनेट में कई पद खाली हैं जिन्हें भरने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सही समय पर निर्णय करेंगे। वहीं, राज्यपाल से मुलाकात

पर उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी बनने के बाद अब तक राज्यपाल से मुलाकात नहीं हो सकी थी इसलिए शिष्टाचार भेंट के नाते राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। दरअसल, राधामोहन की राज्यपाल से मुलाकात की चर्चा ने यूपी में फिर से मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलों को हवा दे दी है। राधामोहन ने शनिवार रात पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह व महामंत्री संगठन सुनील बंसल के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक उनके बीच जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव और राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से मिले दिशा-निर्देश पर चर्चा हुई। राधामोहन रविवार को पार्टी की बैठक भी लेंगे। दरअसल, छह महीने बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी कैबिनेट में फेरबदल होगा और एमएलसी बने एके शर्मा को कैबिनेट में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि, भाजपा के पदाधिकारी इससे इनकार कर रहे हैं लेकिन पार्टी पदाधिकारियों की बैठकें और भाजपा प्रभारी की राज्यपाल से मुलाकात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं।

दूध उत्पादन में बुंदेलखंड बना रहा रिकार्ड, महिलाओं को मिला रोजगार

लखनऊ। योगी सरकार में बुंदेलखंड दूध उत्पादन के क्षेत्र में रोज नए रिकार्ड बना रहा है। यहां महिला किसानों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और उनको अच्छी आमदनी भी होने लगी है। यहां बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी 24 हजार 180 महिलाओं को अपने साथ जोड़कर प्रतिदिन 60 हजार से अधिक दूध का संग्रहण और व्यापार कर रही है। बुंदेलखंड में शुरू हुई इस योजना का लाभ झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट के महिला किसानों को मिल रहा है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने रविवार को कहा कि पिछली सरकारों ने बुंदेलखंड पर कभी नजर नहीं डाली, जिसके कारण यह क्षेत्र पिछड़ा रहा। योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद से ही नई-नई योजनाओं ने बुंदेलखंड की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास को नई राह देने का काम किया। कोविड काल में भी महिलाओं ने दूध का संग्रहण और व्यापार किया। उन्होंने कहा कि सरकार के सबका साथ सबका विकास के नारे

को बुंदेलखंड की महिला किसानों ने चरितार्थ करके दिखा दिया है। उनकी मेहनत रंग लाने लगी है। प्रत्येक दिन दूध के उत्पादन और नवीन तकनीक के जुड़ जाने से कमाई भी पहले से कई गुना अधिक हो गई है। यह सब बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के



माध्यम से संभव हो पाया है। प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिसम्बर, 2019 में कंपनी का उद्घाटन किया था। कंपनी बुंदेलखंड के 5 जनपदों जिसमें झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट के 634 गांव की 24,180 महिला किसानों को लाभ मिल रहा है। कंपनी राष्ट्रीय आजीविका मिशन और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की

ओर से वित्त पोषित है। उन्होंने बताया कि महिला किसानों के खाते में सरकार की ओर से योजना के शुरू होने के बाद से आज तक 84 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। जो सीधे महिला किसानों के खातों में गया है। बुंदेलखंड में वर्षभर दुग्ध बाजार की उपलब्धता और लघु एवं सीमांत दुग्ध उत्पादक महिला किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। दुधारू जानवरों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर प्रवक्ता ने कहा कि योजना के तहत दुधारू जानवरों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक आधारभूत तकनीकी सुविधाओं जैसे उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता का पशु आहार, क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण, कम पानी में पैदा होने वाला हरा चारा, बीज, नस्ल सुधार कार्यक्रम और पशु बांझपन निवारण शिविर भी कंपनी आयोजित करती है। उन्होंने कहा कि बलिनी प्रत्येक गांव में कम्प्यूटराइज्ड प्रणाली से दूध की खरीद का प्रबंध कर रही है। ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने में इसकी बड़ी भूमिका है।

व्यापारियों ने वर्चुअल माध्यम से नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का किया स्वागत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के तत्वावधान में विशाल वर्चुअल सभा के माध्यम से रविवार को नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मुकुन्द स्वरूप मिश्रा का प्रदेश व्यापी स्वागत किया। इस वर्चुअल सभा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष मुकुन्द स्वरूप मिश्रा ने ईश वंदना व दीप प्रज्वलित के साथ प्रारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्याम मोहन दुबे व संचालन प्रदेश युवा महामंत्री जीतू सोनी ने किया। वर्चुअल सभा में जूम एप्स से 758, फेसबुक लाइव से 1309 युवा व्यापारी पदाधिकारियों ने अपने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मुकुन्द स्वरूप मिश्रा के स्वागत में भाग लिया। युवा प्रदेश चेयरमैन राजीव आनन्द व कानपुर युवा उद्योग व्यापार मंडल के चेयरमैन रामेंद्र सिंह रॉकी, नगर अध्यक्ष निखिल गुप्ता, महामंत्री सन्त मिश्रा ने व्यापार मंडल के कार्यालय में अपने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष

मुकुन्द स्वरूप मिश्रा को फूल व मालाएं पहनाने के साथ तलवार भेंट कर जोरदार भव्य स्वागत किया। विशाल वर्चुअल सभा में युवा प्रदेश चेयरमैन राजीव आनंद के साथ प्रदेश अध्यक्ष मुकुन्द स्वरूप मिश्रा ने उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल की सोशल एड्रेस साइट को लॉन्च किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रांतीय अध्यक्ष मुकुन्द स्वरूप मिश्रा ने कहा कि कोविड-19 महामारी में जब व्यापार व सामाजिक संगठन दोनों लुप्त होने लगे। तब युवा व्यापार मंडल ने सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से लगातार मंडलीय बैठ करके प्रदेश के व्यापारियों से संवाद स्थापित करने के साथ उनकी समस्याओं का निराकरण करने का जो कार्य किया है। महामंत्री डॉ दिलीप सेठ ने भी युवाओं को संगठन में समर्पित होकर कार्य करने का आवाहन किया। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आज का युग सोशल नेटवर्किंग का युग है युवा व्यापार मंडल का यह कदम बहुत ही सराहनीय है प्रदेश युवा

अध्यक्ष श्याम मोहन दुबे ने युवाओं को संगठन की रीति और नीति के साथ काम करने का आवाहन किया। प्रदेश युवा महामंत्री मुकेश मोदी ने कहा कि युवा बंदर सेना के रूप में है और मुकुन्द स्वरूप मिश्रा हमारे संगठन के राम हैं इसलिए हमें हर लड़ाई में जीत मिलना सुनिश्चित। स्वागत कार्यक्रम प्रांतीय महामंत्री डॉ दिलीप सेठ, राजेंद्र गुप्ता, युवा के चेयरमैन प्रांतीय चेयरमैन राजीव आनंद, युवा प्रांतीय अध्यक्ष श्याम मोहन दुबे, युवा प्रांतीय महामंत्री जीतू सोनी, मुकेश मोदी, कोषाध्यक्ष अकरम गाजी, प्रांतीय मीडिया प्रभारी योगेंद्र सिंह युवा व्यापारी नेता रमन मिश्रा अभय उपाध्याय निखिल योगेश तिवारी युवा चेयरमैन रामेंद्र सिंह रॉकी, नगर अध्यक्ष निखिल गुप्ता नगर महामंत्री संत मिश्रा संदीप वर्मा संतोष जयसवाल राजीव छाबड़ा मनीष सक्सेना सौरभ सोनी रितेश पांडे अमित गुप्ता आशीष गुप्ता जौनपुर विनय महेश्वरी सहित 68 जिलों व कस्बों से बड़ी संख्या में युवा व्यापारी शामिल हुए।

हनुमान जी की मूर्ति पुनः स्थापित करने की मांग

लखनऊ। राजधानी के इंदिरा नगर ए ब्लॉक स्थित ऊँ शिव शक्ति पीठ शनिदेव मंदिर पर हनुमानजी की मूर्ति पुनः स्थापित करने की मांग की। जिसमें भाजपा प्रवक्ता व पार्षद दिलीप श्रीवास्तव एडवोकेट के खिलाफ दर्ज मुकदमे को समाप्त करने की मांग को लेकर पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए चल रहे क्रमिक अनशन के रविवार को दूसरे दिन एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक सिंह एडवोकेट व संरक्षक योगेंद्र नाथ श्रीवास्तव ने कहा कि योगी सरकार के शासन में हनुमानजी की मूर्ति मंदिर से हटाई गई। इससे थानाध्यक्ष गाजीपुर व एसडीएम सदर की दानवी मानसिकता प्रदर्शित होती है। दिलीप श्रीवास्तव एडवोकेट द्वारा न्यायालय में मंदिर की रक्षा संबंधी मामलों के वाद को अधिवक्ता के रूप में लड़ते हैं। कहा सभी प्रपत्र अधिकारियों को दिखा रहे तो अधिकारियों ने उनसे अभद्रता की। कहा जिसे अधिवक्ता समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रख्यात अधिवक्ता व अयोध्या

मामले की वकील रंजना अग्निहोत्री ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने हनुमानजी की मूर्ति हटा कर हिन्दू समाज को ललकारा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी से उक्त प्रकरण का संज्ञान लेकर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई व हनुमानजी की मूर्ति वापस स्थापित करने की मांग की। लखनऊ की पुलिस कोविड काल का अवसर उठाते हुए अन्याय कर रही है। कमिश्नर प्रणाली में सबसे ज्यादा अधिवक्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सभी हनुमानजी की मूर्ति की पुनः स्थापना के लिए क्रमिक अनशन में शामिल हुवे हैं। उपाध्यक्ष प्रमिला मिश्रा, संयुक्त मंत्री रोहित, अनूप त्रिपाठी, सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष ब्रजेश सिन्हा, पूर्व मंत्री नूपेंद्र पांडेय, पूर्व संयुक्त सचिव उपेंद्र प्रताप सिंह, लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व संयुक्त सचिव कामिनी ओझा, अजित सिंह ने भी मुख्यमंत्री से पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मंदिर के पुजारी सत्यप्रकाश मिश्र ने पुलिस लाइन में रखे हनुमान जी की पूजा व भोग लगाने की अनुमति की मांग भी की।



उत्तराखण्ड शासन

घबराये नहीं

कोविड महामारी में डेंगू से सतर्क रहें



तेज सिंह रावत
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

स्वयं रहें सुरक्षित, दूसरों को स्वयं सुरक्षित

ध्यान दें!

- ▶ डेंगू स्वतः ही ठीक होने वाला रोग है।
- ▶ डेंगू के लक्षण होने पर चिकित्सक का परामर्श लें
- ▶ बिना चिकित्सक के परामर्श के कोई भी दवा न लें।



डेंगू के लक्षण

- तेज बुखार, तेज सरदर्द, पीठ दर्द, जोड़ों, मांसपेशियों और शरीर में दर्द, आंखों में दर्द।
- त्वचा पर चकत्ते/लाल निशान।
- मसूड़ों व नाक से खून बहना।

डेंगू से बचाव के उपाय

- 1 डेंगू के मच्छर को पनपने से रोकने के लिए अपने घर में साफ-सफाई रखें एवं आसपास पानी एकत्रित न होने दें।
- 2 रूम कूलर तथा फूलदान आदि का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह खाली कर फिर से भरें।
- 3 पानी की टंकियों को सही तरीके से ढक कर रखें ताकि मच्छर उसमें प्रवेश न कर सकें।
- 4 मच्छर से बचने के लिए पूरी बाजू वाले व शरीर को ढकने वाले वस्त्र पहनें।
- 5 प्रयोग में न लाये जाने वाले पात्र, कबाड़, टायर, नारियल के खोखे इत्यादि को नष्ट कर दें।

हम सब साथ मिलकर कोविड महामारी से
लड़ते हुए डेंगू से बच सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नं. 104 (टोल फ्री) पर सम्पर्क करें।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी



सपा नेता मौसम अली ने जिलाधिकारी हरिद्वार को पत्र प्रेषित कर कोविड कर्फ्यू में की छुट देने दरगाह के कपाट खोलने की मांग

अमर उजियारा संवाददाता

पिरान कलियार। सपा नेता मौसम अली ने जिलाधिकारी हरिद्वार को पत्र प्रेषित कर कोविड कर्फ्यू में छुट देने तथा कलियार में बंद पडी 19 तीन दरगाहों के कपाट खोलें जान की मांग की है। कोविड 19 की दुसरी लहर ने देशभर में रोजगार की कमर तोड़ दी है। तथा दरगाह के कपाट बंद होने से कलियार क्षेत्र के सभी दुकानदार बेरोजगार हो गए जिससे आर्थिक स्थिति भी खराब हो चुकी है जिसके चलते सपा नेता मौसम अली ने जिलाधिकारी हरिद्वार



को पत्र प्रेषित कर कोविड कर्फ्यू में छुट देने तथा पिरान कलियार में बंद

पडे दरगाहों के दरवाजे खोलें जानें की मांग की है। मौसम अली ने पत्र में लिखा है की उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू में अधिक छुट दी है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार भी कोविड कर्फ्यू में छुट दे। जिसे बेरोजगार लोग अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत हो सकें। कलियार क्षेत्र के दुकानदारों ने सपा नेता मौसम अली को सबसे पहले कोविड-19 कर्फ्यू में छुट देने और दरगाह के कपाट खोलने की मांग से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ रही है मौसम अली को कहा तुम एक बधाई के पात्र हो

लाखों की चोरी की घटना का 24 घंटे में कलियार पुलिस ने खुलासा कर तीन चोरों को पहुंचाया जेल

अमर उजियारा संवाददाता

पिरान कलियार। पुलिस ने लाखों चोरी की घटना का 24 घंटे में खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी किये गए 54 जस्टी क्रैश पोस्ट बैरियर एक पिकप गाड़ी समेत बरामद किए हैं क्रैश पोस्ट बैरियर की कीमत करीब एक लाख 90 हजार बताई गई है, पिरान कलियार थाना अध्यक्ष धर्मेन्द्र राठी ने बताया कि 3 जून को व सुधीर कुमार पुत्र घनश्याम निवासी आर्य नगर ज्वालापुर द्वारा तहरीर देकर बताया था कि 2 जून की रात्रि उससे कार्यस्थल रहमतपुर गांव के पास नौ गजा पीर की मजार के सामने से 54 जस्टी स्टील क्रैश बैरियर चोरी हो गए हैं मामले में मुकदमा दर्ज कर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर टीम का गठन किया गया। गठित की गई थी मैं मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की तो तीन आरोपी अमजद पुत्र जरीफ निवासी बढेरी राजपूतान थाना बहादुराबाद मुरसलीन पुत्र सलीम, रियाज पुत्र फैयाज दोनों निवासी रहीम कॉलोनी



मौहल्ला पावाधेई थाना कोतवाली ज्वालापुर को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी किये गए 54 जस्टी क्रैश पोस्ट बैरियर एक पिकप गाड़ी समेत बरामद किए हैं। जिसकी कीमत करीब एक लाख 90 हजार

बताई गई है। आरोपियों को पकड़ने वाली टीम में धर्मेन्द्र राठी, उप निरीक्षक नीरज मेहरा, कॉन्स्टेबल हनीफ, तेजपाल सिंह, देवी प्रसाद, शाहआलम, सुबोध कुमार, अलियास आदि शामिल रहे।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कलियार थाना प्रभारी धर्मेन्द्र राठी व सपा नेता मौसम अली हाजी खालिद अहमद ने नीम का पेड़ लगाकर वृक्षारोपण का स्टेशन दिया



अमर उजियारा संवाददाता

पिरान कलियार। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया

जा रहा है, इस दिवस को मनाने का केवल एक ही मकसद है, प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक करना उसके महत्व के बारे में लोगों को बताना। आज थाना

आर्थिक सहायता के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ाने की मांग

रुडकी। कोविड 19 संकट के कारण लागू कोरोना कर्फ्यू से व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नगर निगम की ओर से गरीब दुकानदारों एवं कामगारों की आर्थिक सहायता के लिए आवेदन फार्म वितरित किए जा रहे हैं। रामनगर पार्श्व ने अनुदान राशि के आवेदन करने की तिथि

को बढ़ाने की मांग की है। कोरोना संक्रमण के बाद कोरोना कर्फ्यू के कारण गरीब वर्ग के व्यापारियों को काफी आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है, लेकिन सरकार ने ऐसे वर्ग के व्यापारियों के लिए अनुदान राशि तय की है। जिसके फार्म भी नगर निगम की ओर से वितरित किए जा रहे हैं। जबकि

आवेदन की तिथि अब खत्म हो चुकी है। रामनगर के पार्श्व पंकज सतीजा का कहना है कि प्रचार प्रसार के अभाव के चलते बहुत से लोगों का इसका पता नहीं चल पाया है। पार्श्व ने आवेदन करने की तिथि को बढ़ाने के लिए नगर आयुक्त को पत्र लिखा है।

संक्षिप्त समाचार

हरिद्वार में कोरोना 97 केस

हरिद्वार। एक दिन राहत के बाद जिले में फिर से कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है। रविवार को जिले में कोरोना के 97 नए केस दर्ज किये गए। जबकि 02 लोगों की कोरोना से मौत हुई। रविवार को जिले में कोविड संक्रमितों का आंकड़ा शनिवार की तुलना में बढ़कर 97 हो गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सीसीसी में भर्ती मरीजों का आंकड़ा घटकर 40 रह गया है। जनपद में होम आइसोलेशन में मरीजों की संख्या 2940 हो गयी है जबकि एक्टिव केस घटकर 2648 पर आ गए हैं। अब तक जिले में 49, 846 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। विभिन्न सीसीसी से 26 लोगों को रविवार को डिस्चार्ज कर दिया गया। बीते कई दिनों से कोरोना संक्रमित आने के बाद 490 लोगों को होम आइसोलेशन से भी अवमुक्त कर दिया गया। जिले में अब तक 15 लाख 41 हजार 632 लोगों के कोरोना जांच के लिए सैपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 15 लाख 33 हजार 867 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है। 49 हजार 846 पॉजिटिव दर्ज किए गए हैं जबकि 2960 लोगों की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षा सूची में हैं। रविवार को कोरोना जांच घटकर 6 हजार 236 पर पहुंच गई। जबकि जनपद में कंटैमेंट जोन की संख्या अभी भी 22 बनी हुई है।

संक्रमितों की सुध ले प्रशासन

हल्द्वानी। सेतु सामाजिक विकास समिति ने प्रशासन से मीटाआंवला चौसला में संक्रमितों की सुध लेने की अपील की है। संस्था के अध्यक्ष व पूर्व जिल्द सदस्य नीरत तिवारी ने बताया कि बीते दिनों बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग संक्रमित मिले हैं। कहा कि कई लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। घर में ही आइसोलेट हो सकें, ऐसी स्थिति भी नहीं है। गांव में आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था नहीं है। घरों में छोटे-छोटे बच्चे हैं। ऐसे में उन्हें भी संक्रमण फैल सकता है। कहा कि संस्था की ओर से संक्रमितों को मास्क, सेनेटाइजर उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही अन्य व्यवस्थाओं में भी हाथ बढ़ा रहे हैं।

चामुंडा देवी मंदिर में चोरी पर भड़के लोग

हल्द्वानी। कानिया के चामुंडा माता मंदिर में देर रात हुई चोरी पर भड़के ग्रामीणों ने कोतवाल अबुल कलाम को तहरीर देकर आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। ग्रामीणों ने कोतवाल को बताया कि शनिवार देर रात चामुंडा माता मंदिर में चोरों ने मेन गेट का सरिया, नल के पाइप तोड़ दिए और दान पात्र, आभूषण चुरा ले गए। पास ही बच्चों का प्राइमरी स्कूल और मिनी स्टेडियम की खाली भूमि है, यहां शाम होते ही अवैध कच्ची शराब, स्मैक, गांजे की बिक्री होती है। नशा कर झगड़ा और गाली गलौज होती है, जिससे गुजरने वाली महिलाओं को काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। कोतवाल अबुल कलाम ने बताया कि जांच जारी है। शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्त में होंगे। पत्र में आनंद रावत, ललित मोहन सत्यवली, भगवान सिंह, रमेश पणन, मोहन महारा, कृष्ण कांत सत्यवली, कैलाश तिवारी, गुड्डु पाण्डे आदि के हस्ताक्षर हैं।

ठेकेदार को झांसा देकर खाते से 15 हजार उड़ाये

रुडकी। ठेकेदार को झांसा देकर उसके खाते से 15 हजार की रकम साफ कर दी। आरोपित ने एटीएम कार्ड के सत्यापन का साझा देकर खाते से रकम उड़ाई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला रोड निवासी अरविंद लेबर ठेकेदार है। अरविंद का शहर के एक बैंक में खाता है। अरविंद के मोबाइल पर शनिवार को एक फोन आया था। फोन करने वाले ने बताया कि वह बैंक का कर्मचारी बोल रहा है। उनके एटीएम कार्ड की अवधि समाप्त हो चुकी है। उन्हें अपने एटीएम कार्ड का नवीनीकरण करना होगा। नवीनीकरण के लिए उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फोन करने वाले ने बताया कि वह उनके मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेज रहा है। इस लिंक को ओपन कर वह एटीएम कार्ड के ऑनलाइन नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उसकी बातों में आकर ठेकेदार ने मोबाइल पर आये लिंक को ओपन कर दिया। लिंक को ओपन करते हुए उनके खाते से 15 हजार रुपये की निकासी होने का मैसेज आया। फोन निकासी का मैसेज देख उनके होश उड़ गये। पीड़ित ने इस बावत गंगनहर कोतवाली पुलिस से शिकायत की है। गंगनहर कोतवाली पुलिस का कहना है कि आरोपित का मोबाइल नंबर ट्रेस किया जा रहा है।

कच्ची शराब के साथ पुलिस ने दो को पकड़ा

मंगलौर कोतवाली पुलिस ने अलग-अलग स्थान से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है। मंगलौर कोतवाली के कांस्टेबल राजेश कुमार ने आसफनगर झाल के समीप एक व्यक्ति को प्लास्टिक केन ले जाते देखा। इस पर कांस्टेबल ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह भागने लगा। घेराबंदी कर आरोपित को पकड़ लिया तो उसके पास से पांच लीटर कच्ची शराब मिली। आरोपित ने अपना नाम शाहरुख निवासी तेहलीवाला कोतवाली सिविल गंगनहर रुडकी बताया। वहीं थिथौला गांव के समीप भी पुलिस ने एक युवक को पांच लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम शिवकुमार निवासी थिथौला बताया। पुलिस दोनों ही आरोपितों से पूछताछ कर रही है कि वह शराब कहां से लेकर आए हैं।

32 गांवों में चलाया विशेष टीकाकरण अभियान

रुडकी। स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की टीम ने सोमवार को लक्सर में टीकाकरण से वंचित 45 प्लस वाले लोगों के लिए विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत 20 टीमों ने 32 गांवों में टीके लगाए। सीएमओ, एसडीएम और सीएचसी अधीक्षक ने दिनभर केंद्रों पर घूमकर अभियान की समीक्षा भी की। लक्सर ही नहीं बल्कि पूरे जिले में 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के टीकाकरण की दर काफी कम है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीके लगाने की कवायद में जुटा है। पिछले दिनों प्रशासन ने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की मदद से क्षेत्र में टीकाकरण से वंचित 45 प्लस वाले लोगों का सर्वे कराया था। सर्वे में करीब 4000 लोग चिन्हित किए गए थे। रविवार को इन लोगों को टीके लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की 20 टीमों को 32 गांवों में लोगों को टीके लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रविवार सुबह 9 बजे ही सभी टीमों को निर्धारित गांवों में भेजकर टीकाकरण शुरू करा दिया गया। बाद में सीएमओ डॉ. शंभू कुमार झा, एसडीएम लक्सर शैलेंद्र सिंह नेगी और लक्सर सीएचसी अधीक्षक डॉ. अनिल वर्मा ने गांवों में जाकर अभियान की समीक्षा की। साथ ही लोगों को टीके लगवाने को प्रेरित भी किया।

